of going in for retrenchment of labour?

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, what will happen to the economy?

SHRI P. A. SANGMA: It is the policy of the Government not to resort to any action which will affect a worker. Therefore, the question of offloading the workers or their retrenchment is a very difficult one. Though we recognise the necessity of rationalisation or reorganising the unit, the policy of the Government is not to affect any worker but within the framework of giving protection to the working class if some reorganisation or reployment is required, I think we will have to do that.

DR. NAGEN SAIKIA: Sir, open-cast mining has been creating pollution of land and water and destroying the ecological balance in some parts, including the Margherita area, of upper Assam and, therefore, there is a strong protest against such operation. I want to know from the hon. Minister whether the Government is going to withdraw the open-cast mining system from those areas.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I don't think that it is wise for the country to withdraw any mines as of now. But, as I admitted in the beginning, open-cast mining does affect the ecology and development of a particular area. We are strictly following the guidelines which have been issued by the Ministry of Environment and in future and maintenance of ecology and environment of that area will form a part of the project itself. So far, it has not been done. We have not earmarked any extra money or we have not set apart any money for that. In future, the maintenance of ecology and protection of environment will be a part of the project.

*243. [*The questioner* (*Shri Krishan Lal Sharma*) was absent. For answer *Vide* Col. 32-33 *infra*.]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिये अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध

*244. **श्री राघवजी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोड़ा पछाड़ का पुल टूट जाने के कारण जो यातायात मध्य प्रदेश के अन्य मार्गों से गुजरा और उस कारण उन मार्गों को क्षति हुई, उसको ठीक करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने उन राज्य सड़कों की मरम्मत के लिए, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर घोड़ा पछाड़ पुल टूट जाने के बाद यातायात के लिए उपयोग में लाया गया था, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित की जाने वाली 418.544 लाख रु. की लागत की 27 स्कीमें भेजी हैं।

(ग) चूंकि 13.5.1988 को संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है और पुरानी केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को मिलने वाली निधि में पर्याप्त धन

उपलब्ध नहीं है, अतः इन प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री राघवजी : सभापति जी, राष्ट्रीय राज मार्गों के रखवाली, उनका रख-रखाव और उनकी देखरेख का काम केंद्रीय सरकार का हुआ करता है लेकिन केंद्रीय सरकार की लापरवाही के कारण वर्ष 1990 में वर्षा ऋतु में घोड़ा पछाड़ जो राजमार्ग नंबर 3 पर है, वह पुल टूट गया और पुल के टूटने की वजह से उसका ट्रैफिक अशोकनगर-भोपाल और सम्भर-भोपाल इन मार्गों पर से निकाला। लेकिन ये मार्ग ऐसे नहीं थे कि वह सारे ट्रैफिक को वहन कर पाते। नतीजा यह हुआ कि ये दोनों रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये। जब मध्यप्रदेश सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिये केंद्रीय सरकार से मांग की तो केंद्रीय सरकार ने कहा कि आप सड़क निधि से मांगो। जब सड़क निधि से मांग की गई तो इसका अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पुरानी केंद्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को मिलने वाली निधि में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने जो 4 करोड़ 18 लाख रुपये की जो मांग की है, तो अगर इतना धन उपलब्ध नहीं है तो कितना धन उपलब्ध है?

श्री जगदीश टाइटलर : यह सच है कि नेशनल हाई वे नंबर 3 पर बहुत वर्षों के कारण पुल जो 1867 का था उसके दो हिस्सों को नुकसान हुआ और उसके कारण ट्रैफिक को हमें डाईवर्ट करना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं वे भी नेशनल सड़कें हैं। किसी न किसी रास्ते से ट्रैफिक जायेगा ही। फिर भी नेशनलज हाईवे अथारिटी वालों ने एक रास्ता नदी के नीचे से निकाला और उसका इस्तेमाल किया और दो महीने के अंदर अंदर उस ब्रिज को रिपेयर भी कर दी और वह फिर से ठीक हो गया और उस पर ट्रैफिक चल रहा है। जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा था उसमें से हमने 15.90 लाख अप्रूव कर दिया था। उस अप्रूवल के कारण यह फिर से रिपेयर हो चुका है।

श्री राघवजी : सभापति जी, मैंने पूछा था कि वह निधि कितनी उपलब्ध है, यह माननीय मंत्री जी ने बताया नहीं। 15 लाख उपलब्ध कराने से कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों सड़कें जो सौ-सौ किलोमीटर से ज्यादा है वे पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इसलिये 15 लाख का कोई मतलब नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या वे पूरक बजट में यहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण पूरा रोड नष्ट हो गया है, तो क्या इसके लिये कोई विशेष प्रावधान रखने का आप प्रस्ताव रखेंगे?

श्री जगदीश टाइटलर : जो मुझे पैसा मिलता है उसी के हिसाब से मैंने खर्च करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसे की मांग की 20.90 लाख की कि सड़कों की रिपेयर करनी है स्टेट गवर्नमेंट की सड़कों की रिपेयर्स हमारे अंडर नहीं आती इसलिए जो भी पुल और नेशनल हाइवेज के लिए हमारे पास पैसा है हमने वह लगाकर उसको (व्यवधान) ठीक कर दिया है। ट्राफिक भी चल पड़ी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश देश के राज्यों में सबसे बड़े क्षेत्रफल का प्रदेश है और वह सात राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां सड़कों की कमी है। जो राष्ट्रीय घनत्व है सड़कों का उससे भी इस सड़कों का घनत्व इस प्रदेश में है। यहां पर 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी लम्बाई 2,976 कि०मी० है। 1984 में राष्ट्रीय यातायात कमेटी ने बहुत से नये राष्ट्रीय राजमार्गों को यहां बनाने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष

एक योजना प्रस्तावित की थी। क्या मंत्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि अगली 8वीं पंचवर्षीय योजना में उसको शामिल करने का विचार है और मेरे प्रश्न का "ब" पार्ट है। मेरी जानकारी के अनुसार 1989-90 में 29.95 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों की रिपेयर और उन्नतीकरण के लिए राज्य सरकार को दिया गया, 1990-91 में केन्द्र सरकार के द्वारा 30.93 करोड़ रुपया दिया गया और 1991-92 में 37.50 करोड़ रुपया व्यय किया गया तो यह किसकी जिम्मेदारी है—वहां पर सड़कें और पुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन आते हैं उनका रखरखाव और उन्नतीकरण अगर राज्य सरकार करती है तो केन्द्र सरकार द्वारा अपना पैसा देने के बाद क्या उसके पास कोई ऐसी जांच एजेंसी है जिससे कि वह समय समय पर जांच कर सके कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I want to inform the Member that there is the Pandey Committee which was set up in 1978 which recommended eight national highways for Madhya Pradesh. I am waiting for the 8th Five Year Plan allocation of funds and it is only then I can answer.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kalmadi

SHRI SURESH KALMADI: Sir, the State Government is always asking for additional funds and the Central Government is always short of funds and because of this situation a resolution was passed in Parliament in 1988 whereby five per cent of the budget of Petroleum Ministry would form part of road cess. I would like to know whether the Surface Transport Minister has received some amount from their so far. If not, why not? Has he spoken to the Finance Minister and what is the backlog of amount which is due to the Central Road fund. The price of petrol is Rs. 20/- and the car drivers, the truck drivers, all of them are having a tough time on the road. On the Bombay-Pune road every day four to five deaths are reported. I want to know if the fund is allused to the Surface Transport Ministry because the roads are in a horrible condition.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, it is an important question and I am glad that the hon. Member put the question. The plan money on the cess of petrol from 25 per cent in 1931 has come down to .47 per cent in 1987. Keeping that in view a resolution was passed by the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha in May, 1988. The Finance Minister is just sitting over it... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: How much amount?

SHRI JAGDISH TYTLER: Not just keeping in view what Mr. Kalmadi said, but many Members both from the Lok Sabha and the Rajya Sabha and also the State Chief Ministers have been complaining that the roads are in a terrible condition. I only hope that today, the appeal of Mr. Kalmadi and our appeal would get the funds from the Finance Ministry.

SHRI JAGESH DESAI: How much money is due to him?

MR. CHAIRMAN: Roughly he wants to know the quantum.

SHRI JAGDISH TYTLER: I do not have the exact figures. But it is 5 per cent cess on the sale of petrol and diesel and this runs to over Rs. 300 crores in a year.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, you direct the Finance Ministry... (*Interruptions*) ...

SHRI A. G. KULKARNI: You yourself have been quoted in the Press... (*Interruptions*) ... as having said that the Chairman would intervene... (*Interruptions*) ...

SHRI SURESH KALMADI:, Sir, you should direct the Finance Ministry... (*Interruptions*) ...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, you yourself were quoting Mr. Ayyangar ..(*Interruptions*) ...

SHRI SURESH KALMADI: Sir, it is a resolution of Parliament and the Ministry must look into it... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGESH DESAI: Sir, it is more than five thousand crores. . (*Interruptions*) ...

SHRI SURESH KALMADI: Sir, it is more than five thousand crores.

SHRI JAGESH DESAI: It is more than five thousand crores and I do not know how he says it is only three hundred crores. All the roads there are in a terrible shape... (*Interruptions*) ...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, you quoted Mr. Ayyangar... (*Interruptions*) ... You yourself quoted Mr. Ayyangar in the Central Hall just fifteen minutes back... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGESH DESAI: Sir, we want a half-an-hour discussion on this ... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: That is all right. Now, Anand Prakash Gautam.

SHRI JAGDISH TYTLER: Yes, yes... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: It is Question Hour now and let us follow the rules. I have called Mr. Gautam now... (*Interruptions*) ...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, you quoted Mr. Ayyangar We should also follow him... (*Interruptions*) ...

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति जी, केंद्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है और पुरानी केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश को मिलने वाली निधि में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी के जवाब में यह है कि उन प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए आगे कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निधि में पर्याप्त धन आपकी उन सड़कों के लिए कब तक उपलब्ध होगा जिसमें से आप मध्य प्रदेश की उन मांगों पर विचार करने के लिए आप उसको उपलब्ध कर पायेंगे ?

SHRI JAGDISH TYTLER: Firstly, Sir, I would like to clarify that is more than Rs. 300 crores per year. So, if you take it right from 1988 to 1992, it should cross that and you can calculate... (*Interruptions*) ...

SHRI A. G. KULKARNI: Mr. Minister, you don't feel anything. So much of money is involved and you don't feel anything. Do you feel anything?... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGDISH TYTLER: I feel the most... (*Interruptions*) ...

SHRI SURESH KALMADI: You kindly take it up with the Cabinet... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGDISH TYTLER: Yes.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मेरे सीधे सवाल का मंत्री जी की ओर से जवाब नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : वह तो उनका जवाब दे रहे थे ना। आपका तो अभी देना है।

श्री सभापति : आप आनन्द प्रकाश जी का जवाब दीजिए।

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, the total amount is... (*Interruptions*) ...

SHRI SURESH KALMADI: Sir, you must give a direction... (*Interruptions*) ... Every guideline has failed. You must give a direction to the Ministry.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, let me answer that. Under the old formula of 1923, we are getting 3.5 paise per litre and I would like to inform the Members that the total amount does not exceed Rs. 10 crores to Rs. 11 crores for the whole country and that amount of money we are distributing for the repairs of the roads.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Yashwant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the projects which the Minister is mentioning and which are likely to be taken up as National Highways, obviously, are under the old dispensation, under the old policy. What I would like to know from the Minister is whether, in view of the liberalisation which this Government has brought about, it is the Minister's policy or his Ministry's policy that the National Highways construction will also be made open to the public sector and that more projects would be taken up by or through the private sector in this respect.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, as far as our Ministry is concerned, are keen to open up the construction of the National Highways and Expressways to the private sector. But I cannot do it because there is a lacuna in the law and I am very soon coming up with a little change in the law which will allow us to open up the Highways and Expressways to the private people.

MR. CHAIRMAN: Question No. 245.

*245. [*The questioners (Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare and Shri Bekal Utsahi)* were absent. For answer *vide* Col. 33-34 infra]

MR. CHAIRMAN: Question No. 246. Shri Vithalbhai M. Patel.

Supply of coal to Thermal Power Stations in Gujarat

*246. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:†
SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1088 given in the Rajya Sabha on the 29th July, 1991 and state:

(a) what is the requirement of coal for the Thermal Power Stations in Gujarat;

(b) what is the amount of coal sanctioned by the Central Govern- the total requirement of Gujarat; and

(c) whether there has been adequate supply to the Thermal Power Station in Gujarat against the sanctioned linkage of coal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) According to information furnished by Central Electricity Authority, the require ment of coal for thermal power stations in Gujarat based on their generation target for the period April to November '91 was 68.59 lakh tonnes. Against this demand the linkage given by Standing Linkage Committee was 95.6 lakh tonnes. According to provisional data furnishe by Coal India Lttd., the actual despatch during the same period has been 71.1 lakh tonnes which works out to 103.6 per cent of demand.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Chairman, Sir, Coal India Ltd. has introduced a Cash and Carry scheme for coal from 1st October, 1991. As on 4th November 1991, the Gujarat Electricity Board has paid Rs. 51.25 crores towards advance payment for coal. In spite of this, the coal receipts during October 1991

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Vithalbhai M. Patel.